5. 1982-100 के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हटाना।

6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मंहगाई भत्ते संबंधी त्रिपक्षीय समिति आयोजित करना।

7. अधिकतम सीमा समाप्त करने के लिए बोनस अधिनियम में संशोधन।

8. कृषि श्रमिकों के बारे में एक केन्द्रीय विधान।

9. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का सोपक्षेत्र बढ़ाना तथा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का क्रियान्वयन।

10. प्रवासी/बंधुआ श्रमिकों से संबन्धित कानूनी उपबन्धों को पूर्णतः लागू नहीं किया जा रहा है। उन्हें उचित रूप से लागू किया जाये तथा मौजूदा उपबन्धों को संशोधित किया जाय।

11. एसोसिएशन की स्वतन्त्रता तथा संगठित होने के अधिकार से संबंधित अं.श्र.स. अभिसमयों का अनुसमर्थन।

12. बन्द पड़े रुग्ण औद्योगिक एककों तथा औद्योगिक रुग्णता की इस समस्या से निपटने के लिए व्यवसाय संघों की एसोसिएशन को दोबारा शुरू किए जाने की आवश्यकता।

चावल, गेहूं और चीनी का आयात

1849. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल**: क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने यह पूर्वानुमान लगाया है कि भारत द्वारा इस वर्ष भारी मात्रा में चावल, गेहूं, और चीनी का आयात किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई पूर्वानुमान केन्द्रीय सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Action against hoarders of edible oils

1850. SHRI KAMAL MORARKA: *Will the Minister of* FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether any stringent action would be taken against those who are found guilty of increasing the edible oil prices illegally; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAM PUJAN PATEL): (a) and (b) All States/UTs have been requested to take stringent action against blackmarketeers, hoarders and anti-social elements under the essential Commodities act and other appropriate legislations, to arrest the rise in edible oil prices.

Allotment of Lands to Scheduled Castes in Badli village, Delhi

1851. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that despite the Delhi Administration's Development Commissioner's circular No. F. 21(1)/P/82/5013—65 dated 28th June, 1982, the DDA (Delhi Development Authority) is refusing to hand back the land